राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में गाँव गणराज्य (ग्राम गणराज्य) आंदोलन

राजस्थान में पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में कई गांवों ने खुद को ''गाँव गणराज्य'' घोषित किया है ''ग्राम गणराज्य'' आंदोलन के हिस्से के रूप में और जल, जमीन और जंगल (जल, जंगल और जमीन) जैसे सामुदायिक संसाधनों पर अपने अधिकारों पर जोर देना शुरू कर दिया। डूंगरपुर जिले के गाँव मनथगाँव उन पहले गांवों में से है जिन्होंने 1990 के दशक में खुद को एक गाँव गणराज्य घोषित किया है। अपने गाँव को गाँव गणराज्य घोषित करने के बाद, समुदाय ने ग्राम सभा (जीएस) के सदस्यों को लेकर वन संरक्षण समिति के गठन द्वारा आस–पास के जंगलों को जिसे वे अपना पारंपरिक सामुदायिक जंगल मानते थे, उनके संरक्षण का कार्य संभाल लिया, जिसे अब तक राज्य के वन विभाग (एसएफडी) द्वारा किया जाता था। वन संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को संस्थागत रूप देने, के लिए समुदाय द्वारा नियम और विनियम निर्धारित किए गए थे। लगभग दस से अधिक वर्षों के इसके नियंत्रण और प्रभावी और टिकाऊ उपयोग के बाद, परंपरागत वन प्रजातियाँ स्वाभाविक रूप से उगने लगी हैं, जो स्वस्थ वन क्षेत्र के पुनरुद्धार और उस पर समुदायों द्वारा आजीविका कमाने के लिए आशा का एक संकेत है। स्वामित्व अब भी एसएफडी के पास है, लेकिन लोगों को वन संसाधनों के सीमित उपयोग का अधिकार प्राप्त है और वे नियमों और विनियमों समुदाय और जंगलों की स्थिरता की जरूरतों का ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग करते हैं।

(स्रोतः- राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में एक प्रकरण अध्ययनः गाँव गणराज्य (ग्राम गणराज्य) आंदोलन'' वी अन्नामलाई, हैदराबाद, एनआईआरडी एवं पीआर, 2011 को अध्ययन का सारांश)

राजस्थान पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में प्रशासन को मजबूत करने के लिए नियम बनाता है

एफएसए में पंचायत के स्तर पर अपर्याप्त स्टाफ पेसा के कार्यान्वयन में एक चुनौती रहा है। राजस्थान सरकार ने एफएसए के प्रशासन को मजबूत करने के लिए 2014 में अधीनस्थ सेवा नियम पेश किया जिसके तहत ग्रेड–3 में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की भर्ती को अन्य क्षे त्रों में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।